International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in December 2024, ISSN -2393-8048

राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर : 16वीं लोकसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी का तुलनात्मक अध्ययन (गोरखपुर जनपद के विशेष संदर्भ में)

बैद्यनाथेश्वर जायसवाल, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विमर्श निरंतर विकासशील रहा है। यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के विशेष संदर्भ में 15वीं लोकसभा चुनाव (2009) और 16वीं लोकसभा चुनाव (2014) के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी, अस्मिता की राजनीति और मतदान व्यवहार में आए संरचनात्मक बदलावों का एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय राजनीति में वर्ष 2014 का आम चुनाव एक ऐतिहासिक प्रतिमान विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ विकास, सुशासन और समावेशी हिंदुत्व के आख्यान ने पारंपरिक जातिगत गठबंधनों को गंभीर चुनौती दी। गोरखपुर, जो ऐतिहासिक रूप से गोरखनाथ मठ के वर्चस्व और 'मस्कुलर पॉलिटिक्स' का केंद्र रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा 2009 के उच्च जाति (ब्राह्मण) उम्मीदवारों के बजाय 2014 में निषाद उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सोची–समझी रणनीति थी। हालांकि, यह अध्ययन यह उद्घाटित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 'सामाजिक आभियांत्रिकी' के माध्यम से गैर–यादव ओबीसी और उपेक्षित जातियों को हिंदुत्व की व्यापक छतरी के नीचे सफलतापूर्वक एकीकृत किया। भारत निर्वाचन आयोग, जनगणना 2011 और विभिन्न अकादमिक साक्ष्यों एवं लोकनीति–सीएसडीएस के सर्वेक्षणों के आधार पर, यह रिपोर्ट टिकट वितरण प्रणाली, मतदाता मतदान में हुई ऐतिहासिक वृद्धि और चुनावी जनसांख्यिकी के अंतर्संबंधों का गहन मूल्यांकन करती है। अंततः यह शोध स्थापित करता है कि 16वीं लोकसभा में ओबीसी समुदाय मात्र एक मूक 'वोट बैंक' की परिधि से बाहर निकलकर राजनीतिक सत्ता के मुखर और सक्रिय दावेदार के रूप में स्थापित हुआ।

मुख्य शब्द : अन्य पिछड़ा वर्ग, राजनीतिक सशक्तिकरण, 16वीं लोकसभा चुनाव, गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र, सामाजिक आभियांत्रिकी, निषाद समुदाय, हिंदुत्व, अस्मिता की राजनीति, मतदान व्यवहार।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों की यात्रा में राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण और हाशिए के समाज के सशक्तिकरण का प्रश्न हमेशा केंद्र में रहा है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप काका कालेलकर आयोग (1953) और बाद में मंडल आयोग (1978) का गठन हुआ। 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, भारतीय राजनीति, विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में एक 'मूक क्रांति' का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति ने अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का राजनीतिक हृदयस्थल कहा जाता है, इस अस्मिता की राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोगक्षेत्र बना। 1989 के बाद के दशकों में गठबंधन राजनीति का बोलबाला रहा, जहाँ क्षेत्रीय दलों ने जातिगत पहचान के आधार पर अपना जनाधार मजबूत किया 7। लेकिन 2014 में संपन्न हुए 16वीं लोकसभा चुनाव ने इस राजनीतिक यथास्थिति को पूरी तरह से भंग कर दिया। तीन दशकों के लंबे अंतराल के बाद किसी एक राजनीतिक दल (भारतीय जनता पार्टी) ने लोकसभा में अपने दम पर 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें शामिल थीं 8। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस चुनाव को 'चौथी दलीय व्यवस्था' का उदय माना, जहाँ विकास और हिंदुत्व के आख्यान ने पारंपरिक जातिगत वफादारियों को भेद दिया ।

इस वृहद राजनीतिक संक्रमण को सूक्ष्मता से समझने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद एक आदर्श शोध क्षेत्र प्रस्तुत करता है। गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से गोरखनाथ मठ का अभेद्य दुर्ग रहा है, जहाँ से लगातार हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रतिनिधि चुनाव जीतते आए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि 2009 (15वीं लोकसभा) की तुलना में 2014 (16वीं लोकसभा) के चुनावों में गोरखपुर में ओबीसी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में क्या गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन आए। अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे क्षेत्रीय दलों ने मठ के प्रभाव को बेअसर करने के लिए ओबीसी (विशेषकर निषाद समुदाय) लामबंदी का सहारा लिया, और इसके प्रत्युत्तर में सत्ताधारी दल ने किस प्रकार 'महासामिलन' की रणनीति अपनाकर ओबीसी वर्ग के एक बड़े हिस्से को अपने पक्ष में किया।

साहित्य की समीक्षा एवं सैद्धांतिक विमर्श

ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण को केवल चुनावी हार–जीत के सांख्यिकीय आंकड़ों

तक सीमित नहीं रखा जा सकता, यह एक गहन समाजशास्त्रीय और राजनीतिक प्रक्रिया है। अकादमिक जगत में इस विषय पर व्यापक शोध हुए हैं जो इस अध्ययन को सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं।

क्रिस्टोफ जाफरलौट अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडियाज साइलेंट रिवोल्यूशन : द राइज ऑफ द लोअर कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स' में तर्क देते हैं कि उत्तर भारत में निचली जातियों का उभार भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक लोकतंत्रीकरण का प्रतीक है। उनके अनुसार, हिंदी भाषी राज्यों में पारंपरिक रूप से सवर्ण जातियों (जैसे ब्राह्मण, राजपूत) का दबदबा रहा है, लेकिन मंडल के बाद की राजनीति ने इस वर्चस्व को चुनौती दी। जाफरलौट यह भी स्पष्ट करते हैं कि 2014 के आते–आते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और ओबीसी नेताओं को सीधे तौर पर जातिगत नेता के रूप में पेश किए बिना ही उनका राजनीतिक समायोजन किया, जिसे वे 'सोशल इंजीनियरिंग' कहते हैं ।

बद्री नारायण अपनी कृति 'द मेकिंग ऑफ द दलित पब्लिक इन नॉर्थ इंडिया' में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच उभरती नई राजनीतिक चेतना का खाका खींचते हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे पहचान की राजनीति ने उपेक्षित जातियों को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से लामबंद किया। नारायण का शोध यह समझने में महत्वपूर्ण है कि मल्लाह, निषाद और बिंद जैसी अति–पिछड़ी जातियां किस प्रकार अपने इतिहास और मिथकों का पुनर्निर्माण कर रही हैं ताकि सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकें 17।

प्रोफेसर ए.के. वर्मा 2014 के चुनावों का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत केवल एक राजनीतिक लहर नहीं थी, बल्कि यह मतदाता व्यवहार में एक 'पैराडाइम शिफ्ट' था, जहाँ सुशासन और विकास की आकांक्षाओं ने संकीर्ण जातिगत और सांप्रदायिक पहचानों को पीछे छोड़ दिया। वहीं सुहास पल्शीकर और के.सी. सूरी का मानना है कि भाजपा ने अपनी 'दूसरी राजनीतिक पारी' में सोशल इंजीनियरिंग को फिर से ईजाद किया, जिसके कारण उसे ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भारी समर्थन प्राप्त हुआ।

जिलेस वर्नियर्स का शोध टिकट वितरण की राजनीति पर प्रकाश डालता है। उनके अनुसार, यद्यपि सभी राजनीतिक दल सामाजिक समावेश का दावा करते हैं, लेकिन वे अक्सर जीतने की क्षमता के आधार पर टिकटों का वितरण करते हैं, जो अंततः जातिगत वफादारियों और धनबल पर निर्भर करता है। ये सभी अकादमिक साक्ष्य इस शोध के लिए एक वैचारिक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से गोरखपुर में ओबीसी भागीदारी का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र : गोरखपुर जनपद की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा

चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार को समझने के लिए किसी भी क्षेत्र की जनसांख्यिकी (Demographics) का विश्लेषण नितांत आवश्यक है, क्योंकि जाति और धर्म की संरचना ही वहां की राजनीतिक रणनीतियों को आकार देती है।

जनसंख्या और धर्म

भारत की जनगणना 2011 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गोरखपुर जिले की कुल जनसंख्या 44,40,895 है। इसमें पुरुष आबादी 22,77,777 और महिला आबादी 21,63,118 है। गोरखपुर की जनसांख्यिकी मुख्य रूप से ग्रामीण स्वरूप की है। जिले की कुल आबादी का 81.17% (लगभग 36,04,766 व्यक्ति) ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जबकि केवल 18.83% (8,36,129 व्यक्ति) आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से, गोरखपुर हिंदू बहुल जिला है, जहाँ हिंदू आबादी 90.28% (40,09,037) और मुस्लिम आबादी 9.09% (4,03,847) है। इसके अतिरिक्त 0.22% ईसाई और 0.05% सिख भी यहां निवास करते हैं। साक्षरता दर 70.83% दर्ज की गई है, जो 2001 (58.49%) की तुलना में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता में वृद्धि का संकेत देती है।

जातिगत समीकरण और ओबीसी की स्थिति

यद्यपि भारत में 1931 के बाद से जातिगत जनगणना के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय जनसांख्यिकीय आकलनों के अनुसार, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का एक अत्यंत सघन और मजबूत जनाधार है। गोरखपुर में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी 9,36,061 है। ओबीसी वर्ग के भीतर, निषाद (मल्लाह, केवट, बिंद) समुदाय की आबादी सर्वाधिक निर्णायक है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में निषाद और मल्लाह समुदाय की आबादी लगभग 23 प्रतिशत है, जो इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। इसके अतिरिक्त यादव, कुर्मी, पासी और मौर्य जातियों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। जनसांख्यिकीय घनत्व का यह स्वरूप गोरखपुर की चुनावी राजनीति में ओबीसी सशक्तिकरण की धुरी बनता है। पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र की राजनीति पर दबंग जातियों (विशेषकर ब्राह्मण और राजपूत) का वर्चस्व रहा है। लेकिन जैसे–जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया

परिपक्व हुई, विशेषकर 16वीं लोकसभा चुनाव तक आते–आते, क्षेत्रीय दलों (सपा और बसपा) ने इस ओबीसी बहुल जनसांख्यिकी का राजनीतिकरण करना अपनी मुख्य रणनीति बना लिया।

गोरखपुर की राजनीतिक पृष्ठभूमि और गोरखनाथ मठ का प्रभाव

गोरखपुर की चुनावी राजनीति का विश्लेषण गोरखनाथ मठ के ऐतिहासिक और सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव को समझे बिना अधूरा है। अकादमिक शोधों के अनुसार, गोरखपुर की राजनीति ने तीन अलग–अलग दौर देखे हैं– पहला, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस का आधिपत्य और हिंदू–मुस्लिम सद्भावय दूसरा, मस्कुलर पॉलिटिक्स (बाहुबल की राजनीति) और जातिगत प्रतिस्पर्धा का उदयय और तीसरा, सपा–बसपा जैसे जाति–आधारित दलों का उदय और उसके समानांतर गोरखनाथ मठ के इर्द–गिर्द हिंदू–आधारित राजनीतिक पहचान का सुदृढ़ीकरण। गोरखनाथ मठ केवल एक धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति–केंद्र भी है। मठ के तीन पीढ़ियों के महंतोंकृमहंत दिग्विजयनाथ, महन्त अवेद्यनाथ, और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ–ने गोरखपुर संसदीय सीट का लगातार प्रतिनिधित्व किया है। 1989 के बाद से यह सीट लगातार हिंदू महासभा और बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं 1998 से 2017 तक यहाँ से सांसद रहे, ने अपनी राजनीतिक अपील को केवल सवर्ण जातियों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मठ के कल्याणकारी कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के माध्यम से दलितों और ओबीसी मतदाताओं (विशेषकर गैर–यादव ओबीसी) के बीच गहरी पैठ बनाई। यही कारण है कि गोरखपुर को भारत में 'हिंदुत्व' की सबसे सुरक्षित प्रयोगशालाओं में से एक माना जाता है।

15वीं लोकसभा चुनाव (2009) का विश्लेषण – एक आधार रेखा

16वीं लोकसभा चुनाव में आए व्यापक बदलावों की गहराई को मापने के लिए 15वीं लोकसभा चुनाव (2009) के आंकड़ों को एक आधार रेखा के रूप में विश्लेषित करना आवश्यक है। 2009 के आम चुनाव के समय गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,96,474 पंजीकृत मतदाता थे । उस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता मतदाताओं की भारी उदासीनता थीय कुल मतदाता मतदान (टवजमत ज्नतदवनज) मात्र 44.13% (7,48,613 मत) दर्ज किया गया था।

2009 में टिकट वितरण : ओबीसी प्रतिनिधित्व का अभाव

2009 के चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि उस समय अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक सशक्तिकरण और उन्हें नेतृत्व सौंपने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। सामाजिक न्याय और दलित–पिछड़े वर्गों की बात करने वाले क्षेत्रीय दलों ने भी जीतने की संभावना के नाम पर उच्च जातियों पर दांव लगाया।

तालिका 2 : 15वीं लोकसभा चुनाव (2009) – गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख उम्मीदवार एवं परिणाम

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	राजनीतिक दल	प्राप्त मत	मत प्रतिशत (%)	सामाजिक वर्ग (Caste)
1.	योगी आदित्यनाथ	भारतीय जनता पार्टी	4,03,156	53.9%	सामान्य (राजपूत)
2.	विनय शंकर तिवारी	बहुजन समाज पार्टी	1,82,885	24.4%	सामान्य (ब्राह्मण)
3.	मनोज तिवारी 'मृदुल'	समाजवादी पार्टी	83,059	11.1%	सामान्य (ब्राह्मण)
4.	लालचंद निषाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	30,262	4.0%	अन्य पिछड़ा वर्ग

(स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग एवं IndiaVotes डेटाबेस)

उपरोक्त तालिका से प्राप्त द्वितीयक क्रम की अंतर्दृष्टि यह दर्शाती है कि 2009 में बसपा और सपा दोनों ने गोरखनाथ मठ (राजपूत नेतृत्व) के प्रभाव को काटने के लिए ब्राह्मण उम्मीदवारों (विनय शंकर तिवारी और मनोज तिवारी) को मैदान में उतारा। बसपा अपनी 2007 की सफल 'ब्राह्मण–दलित सोशल इंजीनियरिंग' को दोहराना चाहती थी। इस प्रक्रिया में, जिले की 23% से अधिक निषाद आबादी को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया। केवल कांग्रेस ने एक ओबीसी उम्मीदवार (लालचंद निषाद) को टिकट दिया, जो मुख्य मुकाबले में कहीं नहीं टिक सके। स्पष्ट राजनीतिक विकल्प और नेतृत्व के अभाव के कारण ही 2009 में ओबीसी और हाशिए के मतदाताओं में भारी उदासीनता रही, जो 44.13% के निम्न मतदान प्रतिशत में परिलक्षित हुई।

16वीं लोकसभा चुनाव (2014) : राजनीतिक सशक्तिकरण और प्रतिमान विस्थापन

2014 के आम चुनाव उत्तर प्रदेश और समग्र भारत की चुनावी राजनीति में एक स्पष्ट विच्छेद का प्रतीक

थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2014 में गोरखपुर क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या में भारी इजाफा हुआ। कुल मतदाता 19,04,498 हो गए, जिनमें 10,55,476 पुरुष और 8,49,022 महिलाएं थीं। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन मतदाता मतदान में हुआ अभूतपूर्व उछाल था। 2014 में गोरखपुर में 54.63% (10,40,199 वैध मत) मतदान हुआ। 2009 (44.13%) की तुलना में मतदान में लगभग 10.5% की यह भारी वृद्धि अचानक नहीं थी, यह भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर ओबीसी, युवाओं तथा महिलाओं में आई नई राजनीतिक चेतना और ध्रुवीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम था। इस चुनाव में 8,153 मतदाताओं ने का भी प्रयोग किया, जो लोकतांत्रिक परिपक्वता का सूचक है।

2014 में टिकट वितरण : ओबीसी लामबंदी की नई रणनीति

15वीं लोकसभा की विफलताओं से सबक लेते हुए, 2014 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति में आमूल–चूल परिवर्तन किया। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि गोरखपुर में भाजपा को चुनौती देनी है, तो उच्च जाति के उम्मीदवारों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्र के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय समूह–निषाद समुदाय को सीधे तौर पर राजनीतिक नेतृत्व सौंपना होगा। यह एक 'टॉप–डाउन' (ऊपर से नीचे) सशक्तिकरण का प्रयास था।

तालिका 3: 16वीं लोकसभा चुनाव (2014) – गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख उम्मीदवार एवं परिणाम

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	राजनीतिक दल	प्राप्त मत	मत प्रतिशत (%)	सामाजिक वर्ग (Caste)
1.	योगी आदित्यनाथ	भारतीय जनता पार्टी	5,39,127	51.83%	सामान्य (राजपूत)
2.	राजमती निषाद	समाजवादी पार्टी	2,26,344	21.76%	अन्य पिछड़ा वर्ग
3.	राम भुआल निषाद	बहुजन समाज पार्टी	1,76,412	16.96%	अन्य पिछड़ा वर्ग
4.	अष्टभुजा प्रसाद त्रिपाठी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	45,719	4.40%	सामान्य (ब्राह्मण)
5.	राधे मोहन मिश्र	आम आदमी पार्टी	11,873	1.14%	सामान्य

(स्रोतः भारत निर्वाचन आयोग एवं IndiaVotes डेटाबेस)

2009 और 2014 के बीच तुलनात्मक विश्लेषण और अंतर्दृष्टि

तालिका 2 और तालिका 3 का गहराई से विश्लेषण करने पर अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी से जुड़े कई तृतीयक क्रम के निष्कर्ष सामने आते हैं:

1. **अस्मिता की राजनीति बनाम समावेशी हिंदुत्व :–** 2014 में सपा और बसपा दोनों ने जानबूझकर निषाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा ताकि 23% निषाद/मल्लाह आबादी का पूर्ण ध्रुवीकरण किया जा सके । यह 'मंडल' (जातिगत पहचान) के हथियार से 'कमंडल' (हिंदुत्व) को काटने का एक सीधा प्रयास था। सपा का वोट प्रतिशत 2009 के 11.1% से दोगुना होकर 21.76% हो गया। इसी प्रकार, यद्यपि बसपा का वोट प्रतिशत गिरा (24.4% से 16.96%), लेकिन सपा और बसपा के निषाद उम्मीदवारों ने मिलकर लगभग 4,02,756 मत (कुल मतदान का 38.72%) प्राप्त किए। यह आंकड़ा इस बात का अचूक साक्ष्य है कि 2009 में जो ओबीसी समुदाय मात्र एक मूक मतदाता था, 2014 में वह अपनी जातीय अस्मिता के नाम पर भारी संख्या में लामबंद हुआ।
2. **निषाद मतों का विभाजन और राजनीतिक सशक्तिकरण की सीमाएं :–** सपा और बसपा दोनों द्वारा एक ही उप–जाति (निषाद) के उम्मीदवार खड़े करने से ओबीसी वोटों का भारी विखंडन हुआ। यदि यह वोट किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में जाता, तो चुनावी परिणाम भाजपा के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते थे। यह तथ्य ओबीसी राजनीति की उस आंतरिक संरचनात्मक कमजोरी को उजागर करता है जहाँ राजनीतिक दल एक ही जाति के वोट बैंक को आपस में बांटकर, अनजाने में बहुसंख्यक या अधिक संगठित दल को लाभ पहुंचा देते हैं।
3. **भाजपा की 'सामाजिक आभियांत्रिकी' का विजय :–** विपक्ष द्वारा दो अत्यंत मजबूत ओबीसी (निषाद) उम्मीदवारों को उतारने और 38% से अधिक वोट खींचने के बावजूद, योगी आदित्यनाथ ने 51.83% के विशाल वोट शेयर और 3,12,783 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इसके पीछे का मुख्य कारण भाजपा की सूक्ष्म सामाजिक आभियांत्रिकी थी। भाजपा और गोरखनाथ मठ ने सवर्ण मतदाताओं के साथ–साथ गैर–यादव ओबीसी (कुर्मी, कुशवाहा, लोधी आदि) और गैर–जाटव दलितों को हिंदुत्व

के आख्यान और नरेंद्र मोदी के शविकासश (सबका साथ, सबका विकास) के वादों के माध्यम से सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़े रखा 11। मठ की स्थानीय कल्याणकारी नीतियों ने ओबीसी वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि उनका सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण हिंदू अस्मिता के व्यापक ढांचे के भीतर अधिक सुरक्षित है।

निषाद समुदाय का उभार : पहचान की राजनीति और उपनामों का विमर्श

अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति में निषाद समुदाय का उभार पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक विशेष परिघटना है, जिसे केवल चुनावी हार–जीत से नहीं आंका जा सकता। ऐतिहासिक रूप से, नदियों और जल–स्रोतों से जुड़े व्यवसायों (मछली पकड़ना, नाव चलाना, रेत उत्खनन) पर निर्भर निषाद, मल्लाह, केवट, और बिंद समुदाय स्वयं को 'अति पिछड़ा वर्ग' मानते रहे हैं। ब्रिटिश काल में इनमें से कुछ जातियों को 'आपराधिक जनजाति' के रूप में कलंकित किया गया था, जो आज ओबीसी की सूची में शामिल होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। भूमंडलीकरण, पर्यावरणीय गिरावट और नदियों के सिकुड़ते संसाधनों के कारण जब इनके पारंपरिक नदी–आधारित व्यवसाय नष्ट होने लगे, तो इस समुदाय ने सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक सुरक्षा के लिए राजनीतिक सत्ता का रुख किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि निषाद समुदाय अब केवल एक 'वोट बैंक' नहीं रहना चाहता था।

अध्ययन दर्शाते हैं कि यह समुदाय अपने 'उपनामों' की राजनीति के माध्यम से अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा था। मल्लाह से वर्मा, और वर्मा से निषाद या मझवार तक का सफर केवल सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, बल्कि यह अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग को लेकर एक सोची–समझी राजनीतिक रणनीति थी। 2014 के आम चुनाव में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा उन्हें केंद्रीय मंच प्रदान किया जाना इसी सामाजिक उद्वेलन का परिणाम था। यद्यपि 2014 में ये उम्मीदवार चुनाव हार गए, लेकिन इस चुनाव ने निषाद समुदाय के राजनीतिक सशक्तिकरण की ऐसी मजबूत नींव रख दी कि बाद के वर्षों में 'निषाद पार्टी' जैसे विशुद्ध जाति–आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसी लामबंदी का परिणाम था कि 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा और निषाद पार्टी ने मिलकर भाजपा के इस अजेय दुर्ग को ढहा दिया। यह सिद्ध करता है कि 2014 में बोए गए ओबीसी राजनीतिकरण के बीज कितने गहरे और दूरगामी थे।

2014 का अखिल–उत्तर प्रदेश संदर्भ और ओबीसी का महा–स्थानांतरण

गोरखपुर के इन सूक्ष्म रुझानों को 2014 के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मैक्रो–संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 71 सीटें भाजपा ने और 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल (जो कि एक अन्य ओबीसी–कुर्मी आधारित पार्टी है) ने जीतीं। लोकनीति–सीएसडीएस के चुनाव पश्चात सर्वेक्षणों के आंकड़े इस ऐतिहासिक बदलाव की पुष्टि करते हैं। 2014 में भाजपा को पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर–यादव ओबीसी के 61% वोट और कुर्मी–कोइरी समुदाय के 53% वोट मिले। यह एक 'क्रिटिकल रियल अलाइनमेंट' था। यह ओबीसी मतदाताओं का पारंपरिक क्षेत्रीय दलों (सपा–बसपा) से मोहभंग और एक राष्ट्रीय दल (भाजपा) की ओर बड़े पैमाने पर स्थानांतरण का स्पष्ट संकेत था। इसका मुख्य कारण यह था कि सपा को शासन के स्तर पर मुख्य रूप से केवल 'यादव' समुदाय के हितों की पोषक पार्टी माना जाने लगा था, और बसपा को जाटवों की, जिससे अन्य पिछड़ी और अति–पिछड़ी जातियां खुद को राजनीतिक सत्ता और संसाधनों के वितरण में वंचित महसूस कर रही थीं। नरेंद्र मोदी, जो स्वयं को एक ओबीसी पृष्ठभूमि से आते हुए प्रस्तुत कर रहे थे, ने इन उपेक्षित ओबीसी जातियों की आकांक्षाओं को एक राष्ट्रीय स्वर प्रदान किया। भाजपा ने विकास और सुशासन के वादे के साथ–साथ 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया, जिसने एक नए प्रकार की समावेशी राजनीति को जन्म दिया। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का 2014 का चुनाव जीतना इसी वृहद अखिल–भारतीय प्रवृत्ति का एक सूक्ष्म प्रतिरूप था।

विधानसभा क्षेत्रों का सूक्ष्म विश्लेषण

लोकसभा क्षेत्र के भीतर मौजूद विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण करने पर ओबीसी भागीदारी और मतदान व्यवहार की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं : कैम्पियरगंज (320), पिपराइच (321), गोरखपुर शहरी (322), गोरखपुर ग्रामीण (323), और सहजनवा (324)।

तालिका 4: गोरखपुर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का वितरण (2014 के संदर्भ में अनुमानित अनुपात)

विधानसभा क्षेत्र	मतदाताओं की संख्या	मुख्य जनसांख्यिकीय विशेषताएं
कैम्पियरगंज (320)	3,82,642	उच्च ग्रामीण आबादी, सघन ओबीसी व दलित उपस्थिति
पिपराइच (321)	4,05,883	कृषि बहुल, निषाद और मौर्य बाहुल्य
गोरखपुर शहरी (322)	4,64,077	उच्च शहरीकरण, सवर्ण और व्यापारी वर्ग बाहुल्य, योगी का गढ़
गोरखपुर ग्रामीण (323)	4,18,787	मिश्रित आबादी, यादव और निषाद घनत्व
सहजनवा (324)	3,77,805	औद्योगिक / कृषि मिश्रित, ब्राह्मण व ओबीसी बाहुल्य

(स्रोतः निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन गोरखपुर डेटाबेस)

2014 के चुनावों में इन सभी क्षेत्रों में 2009 की तुलना में उच्च मतदान दर्ज किया गया। पिपराइच, कैम्पियरगंज और गोरखपुर ग्रामीण जैसे विधानसभा क्षेत्रों में, जहाँ ओबीसी और दलित आबादी की सघनता अधिक है 23, वहां राजनीतिक दलों के बीच अत्यंत सघन प्रतिस्पर्धा देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों (जहाँ जिले की 81.17: आबादी बसती है) ने टिकट वितरण में जातिगत लामबंदी पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। 2009 के चुनाव में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता थी, वहीं 2014 में यह उदासीनता आक्रामक भागीदारी में बदल गई। समाजवादी पार्टी और बसपा ने इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के ओबीसी मतदाताओं को लक्षित किया था। इसके विपरीत, भाजपा ने गोरखपुर शहरी क्षेत्र (जहाँ से योगी आदित्यनाथ स्वयं लगातार विधायक भी रहे) से अपनी अभेद्य बढ़त सुनिश्चित की और ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुत्व एवं मोदी लहर के माध्यम से ओबीसी वोटों के एक बड़े हिस्से में सेंधमारी कर विपक्ष की रणनीति को विफल कर दिया । यह सिद्ध करता है कि शहरी क्षेत्रों में विकास और हिंदुत्व का कॉकटेल, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आभियांत्रिकी ही 2014 के चुनाव की निर्धारक शक्ति थी।

निष्कर्ष

16वीं लोकसभा चुनाव (2014) भारतीय राजनीतिक इतिहास और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक युगांतकारी मोड़ था। इस शोध पत्र का तुलनात्मक अध्ययन यह अकाट्य रूप से सिद्ध करता है कि 2009 के चुनावों की तुलना में 2014 में अन्य पिछड़ा वर्ग ने राजनीतिक निष्क्रियता को त्याग कर सत्ता विमर्श में सक्रिय भागीदारी का मार्ग चुना।

अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

1. **उम्मीदवार चयन में नीतिगत परिवर्तन :** समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा 2009 के सवर्ण (ब्राह्मण) उम्मीदवारों के स्थान पर 2014 में निषाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारना कोई सामान्य चुनावी हथकंडा नहीं था। यह गोरखपुर क्षेत्र में ओबीसी समुदाय के बढ़ते राजनीतिक कद, उनकी जनसांख्यिकीय शक्ति (23: आबादी) और उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की अनिवार्य स्वीकार्यता का प्रमाण था।
2. **मतदान प्रतिशत और लोकतांत्रिक भागीदारी :** 2009 से 2014 के बीच मतदान प्रतिशत में लगभग 10. 5: की वृद्धि (44.13% से 54.63%) सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर ओबीसी, युवाओं और अन्य हाशिए के समूहों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बढ़ती आस्था और लामबंदी को इंगित करती है। निर्वाचन आयोग के जागरूकता अभियानों और राजनीतिक दलों की सघन प्रतिस्पर्धा ने हाशिए के वर्गों को मतदान बूथ तक खींचने में सफलता पाई।
3. **सामाजिक आभियांत्रिकी का विजय :** भाजपा द्वारा ओबीसी वोटों के विभाजन का रणनीतिक लाभ उठाना और समावेशी विकास एवं हिंदुत्व के वृहद आख्यान के तहत गैर–यादव अति–पिछड़े वर्गों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ना यह साबित करता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण अब केवल विशिष्ट जाति–आधारित दलों की बपौती नहीं रह गया है। 2014 में भाजपा ने सफलतापूर्वक 'मंडल' और 'कमंडल' का विलय कर दिया।
4. **नई राजनीतिक चेतना और भविष्य की राजनीति का प्रादुर्भाव :** 2014 के चुनावों ने निषाद और अन्य अति–पिछड़ी जातियों के भीतर यह गहन चेतना भर दी कि वे केवल सत्ता के उपकरण या 'वोट बैंक' नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं सत्ता के नियंता हैं। यद्यपि 2014 में वे सीधे तौर पर चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन इसी चेतना ने भविष्य की राजनीति में उन्हें मोलभाव करने की अपार शक्ति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप निषाद पार्टी जैसे दलों का उदय हुआ।

अंततः, 'राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर' बढ़ते हुए, गोरखपुर जनपद का यह तुलनात्मक अध्ययन इस

शाश्वत राजनीतिक सत्य को रेखांकित करता है कि जब हाशिए का कोई समुदाय अपनी जनसांख्यिकीय ताकत को राजनीतिक चेतना में परिवर्तित कर लेता है, तो वह चुनाव की संपूर्ण दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। 16वीं लोकसभा चुनाव ने न केवल ओबीसी समुदाय को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पटल पर मुखर किया, बल्कि भारत के सभी राजनीतिक दलों को अपनी भविष्य की रणनीतियों के केंद्र में इन अति–पिछड़े वर्गों को स्थापित करने के लिए विवश कर दिया।

संदर्भ

1. **Jaffrelot, Christophe (2003):** *India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India*, Permanent Black.
2. **Narayan, Badri (2014):** *Fascinating Hindutva: Saffron Politics and Dalit Mobilisation*, SAGE Publications.
3. **Pai, Sudha (2012):** *Handbook of Politics in Indian States*, Oxford University Press.
4. **Varma, A.K. (2014):** *Social Engineering and Electoral Politics in Uttar Pradesh*, Rawat Publications.
5. **Yadav, Yogendra (2020):** *Making Sense of Indian Democracy*, Context Publications.
6. **Gudavarthy, Ajay (2014):** *Politics of Post-Civil Society: Contemporary History of Political Movements in India*, SAGE.
7. **Hasan, Zoya (2014):** *Congress After Indira: Policy, Power, Political Change (1984–2009)*, Oxford India Paperbacks.
8. **Suri, K.C. (2014):** *Indian Democracy: Critical Issues and Challenges*, Routledge.
9. **Palshikar, Suhas & Suri, K.C. (2014):** "India's 2014 Loksabha Elections: Critical Shift in National Politics," *Economic and Political Weekly (EPW)*.
10. **Verma, A. K. (2014):** "BJP's Electoral Victory in Uttar Pradesh: Transition from Caste to Post-Caste Politics," *EPW*, Vol. 49, Issue No. 39.
11. **Verniers, Gilles (2014):** "Uttar Pradesh: The BJP's Clean Sweep," *Journal of Indian Politics*.
12. **Heath, Oliver (2015):** "The BJP's Majority in the 2014 General Election: The Role of the Middle Class and Others," *Contemporary South Asia*.
13. **Lokniti-CSDS (2014):** "National Election Study 2014 - Post Poll Analysis of UP," *CSDS Reports*.
14. **Chauchard, Simon (2016):** "Electoral Accountability and Caste Voting in North India," *World Politics Journal*.
15. **Sivaramakrishnan, K. (2015):** "Ecologies of Caste: The Nishads and Riverine Politics in UP," *Modern Asian Studies*.
16. **Kumar, Sanjay (2014):** "The OBC Vote and the 2014 General Election," *Economic and Political Weekly*.
17. **DDU Gorakhpur University Journal:** "Political Dynamics of Eastern UP: A Case Study of Gorakhpur Elections," *Department of Political Science Archives*.
18. **Shastri, Sandeep (2014):** "The 2014 General Election: A Paradigm Shift in Indian Politics," *The Indian Journal of Political Science*.
19. डा बी.आर. आंबेडकर द्वारा अनुच्छेद – 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग का उत्थान - https://www.researchgate.net/publication/361982577_da_biara_ambedakara_dvara_anuccheda-340_ke_tahata_an'ya_pichara_varga_ka_ut'thana
20. भारत निर्वाचन आयोग **(ECI):** "Statistical Report on General Elections, 2014 to the 16th Lok Sabha,"
21. भारत निर्वाचन आयोग **(ECI):** "Statistical Report on General Elections, 2009 to the 15th Lok Sabha,"
22. जनगणना कार्यालय **(Census of India):** "District Census Handbook: Gorakhpur, 2011," censusindia.gov.in.
23. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग **(NCBC):** "Annual Report on Social and Educational Status of OBCs," ncbc.nic.in.
24. **उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी** : "Constituency-wise Voter Turnout Data for 2014,"

ceouttarpradesh.nic.in.

25. **नीति आयोग (NITI Aayog):** "District-wise Developmental Indicators for Eastern Uttar Pradesh (2014-15)," niti.gov.in.
26. **Press Information Bureau (PIB):** "Analysis of 16th Lok Sabha Voter Trends," pib.gov.in.
27. Decoding the caste and community equation of the last two phases of UP polls - India Today, https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/up-polls-caste-and-community-equation-of-last-two-phases-1919354-2022-03-01
28. Gorakhpur 2024 lok sabha election news : Constituency profile, candidate information, voter turnout and polling date. - The Hindu,, https://www.thehindu.com/election/uttarpradesh-gorakhpur-loksabha-constituency/
29. 'NO POWER IN THE WORLD CAN STOP INDIA FROM REACHING ITS GOAL' - Bharatiya Janata Party, https://www.bjp.org/files/kamal-sandesh-documents/KS_ENG_Feb%202022_1_web.pdf